राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nird.org.in

संख्या : 269

प्रगति

अक्तूबर 2017

- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास
- नीति प्रयोजन और समर्थन
- प्रौद्योगिकी अंतरण
- शैक्षणिक कार्यक्रम

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत की ओर एक कदम

3 स्वच्छ भारत मिशन
हम समापन रेखा के कितने करीब है ?

विषयक्रम

6
वैकल्पिक सततयोग्य आजीविकाओं के माध्यम से समग्र विकास

8
सूक्ष्म वित्त पर राष्ट्रीय सेमिनार

9
मिशन अंत्योदया, ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

10 & 11
एन आई आर डी एवं पी आर के कार्यक्रम
एन आई आर डी एवं पी आर में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह

12
सामाजिक एवं व्यवहारात्मक परिवर्तन संचार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

13
ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त सततता और स्वच्छ भारत मिशन पर प्रशिक्षण

14
समुदाय उन्मुख ग्रामीण विकास पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

15
सूचना प्रौद्योगिकी एवं परियोजना प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

16
बी वी बी वी - एन आई आर डी एवं पी आर में हिन्दी दिवस समारोह

17
नागारम समूह के सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा पर परामर्शी बैठक

18
उद्धीपना पहल के तहत प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए प्रारंभिक बाल शिक्षा शास्त्र पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

19
ग्रामीण भारत में जेंडर और कार्य पर प्रोफेसर रितु दीवान द्वारा विशेष व्याख्यान

स्वच्छ भारत मिशन
हम समापन रेखा के कितने करीब हैं ?

मिशन की शुरुआत से तीन वर्ष (2 अक्तूबर, 2014 से 2 अक्तूबर, 2017) बीत चुके है। स्वच्छ भारत, अवश्य ही, एक बड़ा लक्ष्य है। हमारा तत्काल लक्ष्य खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना है । हम समापन रेखा के कितने करीब है ? आइए आंकडों पर नजर डालें। आज भारत में 2.75 लाख से भी अधिक गाँव खुले में शौच से मुक्त (ओ डी एफ) है ; 225 ओ डी एफ जिले ; और 7 राज्यों ने स्वयं को ओ डी एफ घोषित कर लिया है । इसका मतलब है कि इन राज्यों में खुले में शौच करने की पद्धति पूर्णत: समाप्त हो चुकी है । पिछले तीन वर्षों के दौरान हमने 32% प्रगति हासिल की है । यदि हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से पहले बने हुए शौचालयों की संख्या को एस बी एम - जी के उपरांत निर्मित शौचालयों के साथ जोडेंगे, तो हम कह सकते है कि आज ग्रामीण भारत के 70% परिवारों में शौचालय है। ये एक बहुत बडी छलांग और शानदार उपलब्धि है ।

सिक्किम और केरल जो कि काफी समय से ओ डी एफ राज्यों के रुप में प्रचलित है, इनके अलावा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ जैसे अन्य राज्य और संघ शासित प्रदेश है, जो सभी घरों में 100% शौचालय कवरेज करते हुए समापन रेखा तक पहुँच चुके है जबकि बिहार एवं जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य अभी भी 40% कवरेज से भी कम रिपोर्ट दर्शा रहे है । ओडिशा, पुदुचेरी जैसे राज्य 50% से कम कवरेज और उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप जैसे राज्यों में 70% से कम कवरेज रिपोर्ट हुई है। राज्यों को केवल ओ डी एफ घोषित करना काफी नहीं है । वास्तविक चुनौती ओ डी एम स्थिति को बनाये रखने में होती है । अधिकांश राज्य केवल ओडीएफ स्तर हासिल करने पर ही ध्यान दे रहे है। अभी इस समय ग्रामीण स्वच्छता के समक्ष का कार्य है : (i) ओ डी एफ की सततता और (ii) योजना और ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को स्थान पर रखना ।

> **“ राज्यों को खुले में शौच से मुक्त (ओ डी एफ) घोषित करना काफी नहीं हैं वास्तविक चुनौती ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने में है। ”**

वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरु करने से पहले, कुछ स्वतंत्र अनुसंधान समूहो ने यह घोषणा की थी कि यदि हम हर वर्ष 4 से 5 मिलियन शौचालयों का निर्माण करेंगे तो (2044 तक) पूरे भारत में ओ डी एफ स्तर प्राप्त करने के लिए 30 वर्ष लग जाएंगे। अब, एस बी एम अभियान से एस बी एम - जी अवधि के दौरान 4 से 5 मिलियन से बढकर प्रति वर्ष 17 मिलियन शौचालयों का निर्माण हो रहा है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन - जी की प्रगति को देख ने वाले राष्ट्रो के आश्चर्य के लिए। इस मिशन की समय सीमा असाधारण रुप से घट गई है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एम डी डब्ल्यू एस) द्वारा सूचित आंकडों को देखने से लगता है कि, कुछ राज्य 2 अक्तूबर, 2019 तक या उससे पहले ही जैसा कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, गुजरात, केरल आदि राज्यों में हुआ है उसी प्रकार समापन रेखा को छू लेंगे।

छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मेघालय जैसे राज्य ओ डी एफ राज्य घोषित होने के लिए तेजी से समय सीमा के निकट पहुँच रहे है । फिर भी बिहार, जम्मू-कश्मीर,पुदुचेरी एवं ओडिशा जैसे कुछ राज्यों की प्रगति की गति के अनुसार इन राज्यों में 100%, शौचालय कवरेज तक पहुँचने की संभावना नहीं है (जब तक वे तेजी से नीतियों का सही प्रयोग नहीं करेंगे)।

अक्सर कई ओ डी एफ गाँवों को देखने के उत्साह में निर्माण को गति देने लगते है, बाद में यह एहसास होता है कि निर्माण किए गए शौचालयों का या तो दुरुपयोग होता है या फिर उसका प्रयोग ही नहीं होता है । यह एक भी शौचालय न होने की तुलना में एक बहुत गंभीर चिंता है । अगस्त, 2014 में निर्मल ग्राम पुरस्कार (एन जी पी) से पुरस्कृत गाँवों का नमूना सर्वेक्षण करने से पता चला है कि कुछ राज्यों में निर्मित 67% से अधिक शौचालयों का उपयोग कुछ न कुछ कारणों से प्रचलन में नही है । कई स्थानों पर, घटिया गुणवत्ता वाले शौचालयों का निर्माण किया गया है जिसके कारण वे बेकार हो गए है । उनका पुर्ननिर्माण होना आवश्यक है ।

एन जी पी गॉवों के कारणों की जांच से पता चला है मुख्य कारण अपूर्ण स्थापना संबंधी बेकार शौचालय का होना था। अत: कुछ राज्यों में किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन (2014) से बेकार और शौचालयों पर कुछ खतरनाक चित्र देखने को मिला है । ऐसे इतिहास की पुनरावृत्ति न होने की आशा की जा रही है । "लक्ष्य शिकार और सहभागी दृष्टिकोण" दोनों को साथ-साथ आगे बढाने की हमारी इच्छा के कारण विशेषरुप से चिंता का कारण बनी है । अधिकांश राज्य सरकारें सी एल टी एस (समुदाय उन्मुख संपूर्ण स्वच्छत) जैसे सहभागी दृष्टिकोण प्रयोग करने की रिपोर्ट करते है, जिसका उद्देश्य तर्क और कारण के बजाय भावनात्मक प्रेरणा से लोगों को बदला है। विसंगति यह है कि हम एक साथ यात्रा करने के लिए सहभागिता दृष्टिकोण और लक्ष्य चाहते है, जो कि कल्पना से परे है । अगर यह काम करता है, तो यह विकास के अभ्यास में एक नया इतिहास होगा। यदि यह असफल हो जाता है, तो इसे इतिहास दोहराया जाने के रुप में समझा जा सकता है।

शौचालय का उपयोग किस प्रकार किया जाता है यह एक महत्वपूर्ण परिणात्मक सवाल है जो 'यदि स्वच्छता मिशन सफल है या नहीं' का जवाब दे सकता है । हमें एक वर्ष से अधिक पुराने ओ डी एफ गाँवों में प्रचलित नीतियों का अध्ययन करना है और उन्ही का प्रचार-दूसरो से करना है। ये एक तत्काल आवश्यकता है। जो ओ डी एफ सततयोग्य नीतियाँ / योजना पर त्वरित अध्ययन प्रारंभ करने की मांग करती है ।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस डब्ल्यू एस एम) ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए चर्चा प्रदान करने हेतु नीति के रुप में व्यवहार परिवर्तन संचार प्रयोग नीचे आया है। घरेलू शौचालयों का प्रयोग और निर्माण के अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवस्था और अपशिष्ट जल के निपटान आदि जैसे अन्य मुद्दों के लिए स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए सक्षम होना है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन आई आर डी एवं पी आर) ने स्वच्छता व्यवहार और ओ डी एफ स्थिरता मुद्दों पर अनुभवपरक अध्ययन प्रारंभ किया है । सफल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस डब्ल्यू एम) प्रयोगों पर संस्थान ने मामला अध्ययनों का प्रलेखन तैयार किया है। संस्थान ने ग्राम पंचायतों के लिए हस्त पुस्तिका, पास बुक और मॉडल-उप नियमों को प्रकाशित किया है। परिसर में अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त अनुभवों के आधार पर एन आई आर डी एवं पी आर ने स्वच्छ परिसर के लिए एस ओ पी (मानक परिचालन प्रक्रिया) को प्रारंभ किया है। वे सारे संस्थान जो स्वच्छ और हरित परिसर में बदलना चाहते है उनके लिए एस ओ पी से अत्यंत उपयोगी होगा। एन आई आर डी एवं पी आर परिसर में अपनाए गए कुछ अपशिष्ट प्रबधन उपाय निम्नलिखित है।

यदि हमें खाद, जैव-मेथनेशन एवं रीसाईक्लिंग इत्यादि के माध्यम से दूसरा उपयोग का पता चल जाता है तो कचरे को भी संपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। गार्बोलॉजिस्टों ने इसे 'पुर्नप्रयोजन' कहा है। वास्तव में 'कचरे से धन' कहने वाले अधिवक्ताओं का तर्क है कि यह हमारी अभिकल्पना की कमी और नवीनता लाने में अक्षमता है जो हमें जिस उद्देश्य के लिए बने है उस उद्देश्य को पूरा होने के बाद 'अपशिष्ट' के रुप में कुछ वस्तुओं को दिखता है। इसीलिए अपशिष्ट केवल धारणा का ही मामला है। इसे ऐसा आवश्यक रुप से होना नहीं है। हम हमेशा अपशिष्ट से 'पुर्नप्रयोजन'एवं 'पुर्नसृजन' कर सकते है।

एन आई आर डी एवं पी आर ने रसोई अपशिष्ट से परिचालित बॉयोगैस संयंत्र (क्षमता : 15 सी यू एम बलून) की स्थापना की है । इस संयंत्र का डिजाईन इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह हर दिन रसोई घर से 100 किलो रसोई कूडा और 100-120 लीटर अपशिष्ट जल (चावल और सब्जियाँ आदि धोने के लिए प्रयोग किया गया जल) का प्रयोग करने में सक्षम है । इस संयंत्र से हर दिन 7.5 किलो गैस के उत्पन्न की जा सकती है । अर्थात इस संयंत्र में लगभग 15 एल पी जी सिलंडरों (हर महीना) के बराबर गैस उत्पन्न करने की क्षमता है । बॉयो-मिथेन संयंत्र में केवल जैविक हानिवाले कचरे (खाद्य अपशिष्ट एवं सब्जियों को काटने से निकला हुआ कचरा) को टी डाल सकते है । टैंक में उपस्थित जीवाणु जैविक-कूडे को अवायवीय पाचन प्रक्रिया के माध्यम से मिथेन गैस में परिवर्तित करता है । प्रारंभिक जीवाणु क्रियाकलाप के लिए, गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया । उसके बाद से रसोई घर में कटी हुई सब्जियों का 100 किलो कूडा प्रतिदिन संयंत्र में डाला जाता है। परिसर के निवासी कूडे को छांटने के बाद कूडा संग्रहणकर्ताओं को सौंपते है। यदि ऐसे समय में जब हमारे पास रसोई अपशिष्ट के रुप में पर्याप्त फीड-स्टॉक यदि नहीं होता है तब काटे हुए जैव-मॉस/पार्थेनियम के पौधे जैसे तृणों को भी जैव-गैस संयंत्र में डाल सकते है । इस संयंत्र में हर दिन 100-120 लीटर घोल उत्पन्न होता है। इसमें एन पी के होता है । इसका उपयोग जैव-खाद अथवा यदि हम उर्वरकों की तैयारी करते है तो इस उर्वरकों में मिलाया जा सकता है ।

जैव-गैस में 60-80% मिथेन होता है और अवायवीय पाचन नामक प्रक्रिया से इसे तैयार किया जाता है । अवायवीय पाचन में "हरित" ऊर्जा एवं प्राकृतिक उर्वरक के उत्पादन सहित कई पर्यावरणीय लाभ होते है । रसोई कचरे को बयोगैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से कृत्रिम उर्वरकों के लिए एक विकल्प के रुप में काम में आ सकती है, जिससे वातावरण में जारी ग्रीन हाऊज गैस की मात्रा कम हो सकती है । उपयोगी उत्पादों के सृजन और प्रबल ग्रीन हाऊज गैस गड्डे भरने के स्थान से मिथेन का कम जारी होना आदि से अपशिष्ट निपटान संबंधित समस्याओं का निवारण भी होता है । एन आई आर डी एवं पी आर अन्य संस्थानों को स्वच्छ एवं हरित बनने के लिए अपने आप को एक मॉडल के रुप में स्थापित कर रहा है ।

स्वच्छता पखवाडा - 2017

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (एन आई आर डी एवं पी आर) ने हैदराबाद में स्थित स्वयं के परिसर और गोद लिए गए गाँवों में स्वच्छता पखवाडा समारोह - 2017 का आयोजन किया । परिसर में दिनांक 2 अक्तूबर, 2017 को स्वच्छ पखवाडा प्रारंभ किया गया जिसमें सभी संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों द्वारा नव भारत शपथ दिलायी गई और तदनंतर अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषाओं में "क्विट डर्ट" पर लिखित पुस्तक एवं स्टिकर का विमोचन किया गया । परिसर को स्वच्छ एवं हरा-भरा रखने में स्वच्छता कर्मचारियों एवं बगीचे के कर्मचारियों के योगदान के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया गया । स्वच्छता पर नारे लगाते हुए पी जी डी आर डी एम के छात्रों एवं कर्मचारियों द्वारा पूरे राजेन्द्रनगर इलाके तक जुलूस निकाला गया । एन आई आर डी एवं पी आर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आई ए एस ने ध्वज हिलाते झंडा दिखाकर रवाना किया। इसके बाद के दिनों में परिसर की साफ-सफाई, कैम्पस में पार्थेनियम पौधों को उखाडना, आवासों से ई-वेस्ट संग्रहण सहित कई क्रियाकलाप किए गए । एन आई आर डी एवं पी आर महिला मंडली के सदस्यों में "रेड्यूस-रीयूज-रीसाईकिल विचारों" पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । बी वी बी वी स्कूल के बच्चों की सहायता से आर टी पी और बी वी बी वी स्कूल में पौधा रोपण किया गया, भूजल के कर्मचारी सदाय ने भी एन आई आर डी एवं पी आर के स्वच्छता पखवाडे के समारोह में शामिल हुए ।

रामकी ग्रूप, हैदराबाद जो ई-वेस्ट से संसाधन वसूली कार्य से जुडे हुए है, इनके सहयोग से परिसर के आवासों से 2 बार ई-वेस्ट का संग्रहण किया गया। इस अवधि के दौरान एन आई आर डी एवं पी आर में यूनिसेफ, हैदराबाद के सहयोग से स्वच्छता के लिए समुदाय दृष्टिकोण (सी ए एस) में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पर एक नई परियोजना प्रारंभ की गई । सख्त प्रक्रिया के माध्यम से 15 संभाव्य प्रशिक्षार्थियों की शिनाख्त कर उन्हें एन आई आर डी एवं पी आर के सी ए एस में प्रथम प्रशिक्षण दिलाया गया । क्षेत्र स्तरीय सी ए एस व्यवसायी का विकास करने के लिए ये प्रशिक्षार्थी तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक जैसे राज्य सरकारों के लिए पैनल में निहित प्रशिक्षार्थी के रुप में उपलब्ध रहेंगे । परिसर को हमेशा साफ और हरित रखने के लिए एन आई आर डी एवं पी आर में स्वच्छता क्रियाकलाप जारी रहेंगे।

डॉ. आर. रमेश
एसोसिएट प्रोफेसर
ग्रामीण आधारभूत संरचना केन्द्र

वैकल्पिक सततयोग्य आजीविका के माध्यम से समग्र विकास

चौथी शताब्दी बी.सी. में, चाणक्य ने स्पष्ट किया था कि ''धर्मस्थ मूलम अर्थस्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम'' -सही कार्य का मूल सम्पदा है ; अर्थात् सम्पदा है ; अर्थात् सम्पदा का अर्थ उद्यम है - इसीलिए सततयोग्य आजीविका में लोगों को सम्मिलित करना राष्ट्र की जिम्मेदारी है । जैम ट्रिनिटी - जनधन, आधार एवं मोबाईल बैंकिंग सेवाएँ और लघु वित्त बैंकों के लिए धन्यवाद, अब आर्थिक वित्तीय रुप से बाहर रखे गए लोग वित्तीय बाजार, सरकारी एवं बडे पैमाने पर समाज के साथ जुडते हुए अधिक विकल्प पा सकते है । यदि सरकार गरीबों के लिए उचित शिक्षा और स्वस्थ्य सुविधाएँ मुहैय्या करेगी तो भविष्य में कल्याण योजनायें निरर्थक हो जाएगी ।

नीतिगत कार्य

पूर्व एशियायी देशों की तुलना में समाजार्थिक मापदंड पर भारत बहुत ही पिछडा हुआ है। इसके परिणामस्वरुप गरीब और अमीर के बीच की खाई काफी बढ गई है। समग्र विकास के अभाव में, ग्रामीण लोग शिक्षा और निवेश में सीमित आय पर निर्भर होते है । इसे महसूस करते हुए भारत सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), स्व-सहायता समूह बैंक संयोजन कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) आदि को प्रारंभ किया । यह सूचित किया गया है कि लगभग 1.4 मिलियन एकड़ भूमि को एमजीएनआरईजीएस द्वारा खेती के अंतर्गत लाया गया।

बेरोजगार युवाओं को अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने तथा ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2014 में ''आरसेटी'' को प्रारंभ किया । सफल प्रशिक्षण के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से आरसेटी इन प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं के नामों की सूची बैंकों को भेजता है । अक्तूबर, 2017 तक आरसेटी ने देश में 2.37 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित किया (जिनमें से 1.56 मिलियन आत्म निर्भर उद्यमी बन गए) 35 प्रायोजक बैंकों से ग्रामीण युवाओं को रु. 3.31 मिलियन ऋण के वितरण में आरसेटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

वैकल्पिक सततयोग्य आजीविकाओं के सृजन में एस एच जी - बी एल पी मॉडल एक मील का पत्थर है । यह गृह विकसित स्व-सहायता आंदोलन है जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को वित्तपोषण प्रदान करना है । 31 मार्च, 2017 तक स्व-सहायता समूहों ने अपने सदस्यों से रु. 161 बिलियन की कुल धनराशि इकट्ठा की तथा बैंकों से कुल रु. 616 बिलियन (अनुपूरक मुक्त) ऋण उनके पास बकाया थे । एसएचजी - बीपीएल के प्रति धन्यवाद, क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में कर्नूल जिले के छोटे से कस्बे हुस्सैनीपुरम की भिखारिन अब व्यापारी महिलायें बन गई है । अब ये महिलायें फुटपाथ विक्रेताओं की तरह खिलौने, फ्रॉक्स, मसाले इत्यादि बेचती है । तडकाना पल्ली, कर्नूल जिले की जुबेदा बी एक एसएचजी नेता है जिसे ग्रामीणों को स्व उद्यमी बनाने में नेतृत्व करने के लिए नाबार्ड से प्रशंसा मिली । ये एसएचजी महिलायें दूध से दूधपेडा बनाती है ।

सी.के. प्रहलाद ने लिखा है कि किस प्रकार आई सी आई सी बैंक ने भारत में ग्रामीण गरीब महिलाओं को वित्तीय रुप से सशक्त बनाने हेतु एसएचजी - बीपीएल मॉडल पर विश्वास कर ग्रामीण ऋण का विस्तार किया है । देरी से क्यों न हो परन्तु एच डी एफ सी बैंक कश्मीर के स्थानीय लोगों को रोजगार देकर ऋण कारोबार को बढाने में सफल रहा है । एक सर्वेक्षण के अनुसार एसएचजी - बीपीएल के क्रियान्वयन के बाद ग्रामीण गरीबों ने साहूकारों से ऋण लेना कम कर दिया है । ऐसा कहा गया है कि जब आने वाली पीढीयां एसएचजी - बीपीएल के ऋण का प्रभावी उपयोग करेगी तब ग्रामीण गरीबों के जीवन में विकास दिखाई देगा । ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद द्वारा आयोजित अध्ययन के अनुसार एसएचजी सदस्यों की आय 22% तक बढी है । इसीलिए वे अब अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक खर्च कर सकते हैं ।

वैकल्पिक सततयोग्य आजीविका के सृजन की आवश्यकता

भारत में लगभग 85% किसानों का भूमि अधिग्रहण दो हेक्टेयर से भी कम है जिसके कारण उन्हें अर्थ-व्यवस्था मान से वंचित किया जा रहा है । 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में लगभग 120 मिलियन परिवारों को रोजगार मिलता है अर्थात् भारत में लगभग

क्यों यह महत्वपूर्ण है?

480 मिलियन लोगो (4 लोगों की औसतन संख्या लेते हुए) को रोजगार प्रदान किया जाता है । भारतीय कृषि क्षेत्र लम्बे समय से अल्प रोजगार/छद्म बेरोजगारी जैसे मुद्दों से संघर्षरत है । सच तो यह है कि यह क्षेत्र मात्र 140 मिलियन लोगों को ही समर्थन दे सकता है परन्तु अपनी क्षमता से अधिक समर्थन प्रदान कर रहा है । यह सूचित किया गया है कि केरल में पिछले चार वर्षों के दौरान 1.2 मिलियन मजदूरों ने कृषि कार्य को छोड दिया है जिसका मुख्य कारण ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण, कठिन कार्य और मामूली आमदनी का होना है । साईनाथ पलगुम्मी कहते है कि आजीविका के लिए किसान स्वयं को शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के रुप में परिवर्तित कर रहे हैं ।

किसान जिन्हें तथाकथित अन्नदाता कहा जाता है वह भारत में कर्जदार, गरीबी और भूखमरी का शिकार बन रहा है । विकासशील सामाजिक अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित अध्ययन के अनुसार भारत में 2,035 किसान अन्य क्षेत्रों की ओर जा रहे है और बेहतर नौकरी पाने के लिए लगभग 76 प्रतिशत किसान कृषि छोडने के लिए तैयार हैं । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माताओं में यह चिंता बढ रही है कि कृषि क्षेत्र की सततयोग्यता के लिए भारत में वैकल्पिक आजीविका का सृजन करना होगा तथा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने की आवश्यकता है । किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ) को भी एसएचजी - बीएलपी मॉडल की तरह ही बडे पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाए । सहकारिताओं (अमूल, ईफको, मुल्कानूर एवं अन्य) की श्रेष्ठ पद्धतियों को दोहराया जाए ।

कृषि पर दवाब को कम करने के उद्देश्य से सततयोग्य आजीविकाओं के विकल्पों, सूक्ष्म एवं छोटे कारोबारों पर नए सिरे से जोर देना, ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे उभरते क्षेत्रों पर बल (अपशिष्ट से खाद/अपशिष्ट से संपदा) देना । ठोस कुडा प्रबंधन में ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति और गांव में कम से कम चार लोगों के लिए रोजगार (अंशकालिक) सृजन करने की क्षमता है । ग्रामीण बेराजगार युवा खाद्य संसाधित ईकाई (पापड, मसाले, नमकीन इत्यादि), पत्तों की प्लेट बनाना, शहद तैयार करना, नर्सरी, फिनाईल तैयार करना, बुटिक/टेलरिंग शुरु करने पर विचार कर सकते हैं ।

इन परिप्रेक्ष्य में बैंकों को नवोन्मेषी वित्तपोषण मॉडलों के माध्यम से किसानों के साथ-साथ ग्रामीण युवाओं को समर्थन देने में बडी भूमिका निभानी होगी जिससे उनकी क्षमताओं को पूर्ण उपयोग किया जा सके । समग्र विकास क्रियाकलापों में मात्र किसानों पर ही नहीं बल्कि एम एस ई पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि वित्त तक पहुँच से प्रवेश बाधाओं मे कमी, उद्यमशीलता का उन्नयन, स्पर्धा और नवोन्मेषण का कारण बनेगा । इन क्षेत्रों में निवेश के कई अवसर हैं क्योंकि संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला की गतिविधियाँ ऋण सघन होती है । ग्रामीण युवा तिरुपुर में बने हुए वस्त्र, गोदावरी जिले में चावल मिल एवं मोरबी में सेरामिक्स इत्यादि समूह मॉडल का अनुकरण करें । अपने सपनों को साकार करने के लिए युवा अल्पव्ययी तकनोलॉजी का सहारा ले सकते है ।

डॉ. एम. श्रीकान्त
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
वित्तीय समावेश एवं उद्यमशीलता केन्द्र

सूक्ष्म वित्त पर राष्ट्रीय सेमिनार

भारत में ग्रामीण निर्धनों के समाजार्थिक सशक्तिकरण को आगे बढाने में सूक्ष्म वित्त ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । स्व-सहायता समूह (एस एच जी) बैंक संयोजन कार्यक्रम, जो नाबार्ड का एक ब्रेयन चाइल्ड है, बैंकों, एन जी ओ एवं सरकारों के विभिन्न प्रोत्साहक प्रयासों के माध्यम से 1992 से भारत में विकसित हुआ है । एस एच जी - बी पी एल विश्व का सबसे बडा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता का उन्मूलन करना है। वित्तीय समावेश पर नीति फोकस के साथ, सूक्ष्म वित्त विकास प्रतिमान के लिए और महत्वपूर्ण योगदान देने की स्थिति में है ।

नाबार्ड ने वर्ष 2017 में एस एच जी - बैंक संयोजन कार्यक्रम की 25 वीं जयंती मनायी। इस संदर्भ में, विभिन्न स्टेकहोल्डरों को एक साथ लाने, वर्तमान स्थिति का स्टॉक लेने, सूक्ष्म वित्त में उभरते प्रवृत्तियों पर बल देने और भविष्य के कार्रवाई का चार्ट बनाने में मदद करने की दृष्टि से नाबार्ड के साथ सहयोग में एन आई आर डी एवं पी आर ने 16 अक्तूबर, 2017 को एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया ।

सेमिनार में 4 पैनल परिचर्चा हुई और निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :

- वित्तीय समावेशन के युग में एस एच जी - बैंक संयोजन कार्यक्रम बेहतर पद्धतियाँ और बैंको के दृष्टिकोण
- उद्यमशीलता / आजीविका का विकास - सहायक संस्थानों की भूमिका
- नाबार्ड की ई-शक्ति परियोजना - स्टेकहोल्डरों का दृष्टिकोण ; और
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम) एस एच जी आधारित नवीनताओं का निष्पादन और सम्भाविता / बैंकों, सूक्ष्य वित्त संस्थानों शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थानों से प्रतिभागीगण उपस्थित हुए ।

श्री जी. आर. चिन्ताला, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, मुख्यालय, सूक्ष्म ऋण नवाचार विभाग ने सेमिनार का उद्घाटन किया । डॉ. बी.एस. सुरान, प्रबंध निदेशक, एन ए बी एफ आई एन एस, श्री एम. सत्यनारायण रेड्डी, महाप्रबंधक, आन्ध्र बैंक, श्री दुर्गा प्रसाद, एमडी, के बी एस स्थानीय क्षेत्र बैंक, प्रो. दिव्या तेजोमुर्ति, अध्यक्ष ग्रामीण विकास विभाग, नागार्जुन विश्वविद्यालय, श्री रावसाहेब बधे, ल्यूपिन फाऊंडेशन और श्री जी. विद्यासागर रेड्डी, एम डी, स्त्री निधि, तेलंगाना सरकार ने सेमिनार में अपने विचार व्यक्त किए ।

सेमिनार के पैनल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ एस एच जी बैंक संयोजन कार्यक्रम व टेड़ा-मेड़ा भौगोलिक विस्तार, क्षेत्र में उभर रहे एन पी ए, सूक्ष्म उद्यमों एवं आजीविका विकास और संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा की गई । पैनल में ग्रामीण भारत को बदलने का दृष्टिकोण, एस एच जी - बी पी एल, ई-शक्ति आदि जैसे नवीन कार्यो के साथ प्रयोग करने में नाबार्ड की भूमिका पर भी चर्चा की गई । आगे, ग्रामीण उद्यमशीलता के 3 एच अर्थात सूक्ष्म पर्यावरण, सूक्ष्म बाजार एवं सूक्ष्म वित्त पर भी सेमिनार में चर्चा की गई । अंतत: सेमिनार में किस प्रकार स्त्रीनिधि ग्रामीण महिलाओं की सततयोग्य आजीविका के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से उनके जीवन को संचालित कर रहा है पर सत्र चलाया गया ।

डॉ. पी. कोटय्या, भूतपूर्व अध्यक्ष, नाबार्ड ने समापन भाषण प्रस्तुत करते हुए एस एच जी के आधारिक सिद्धांतों को याद किया और आने वाले समय में स्थायी संस्थागत ढांचा बनाने के लिए एस एच जी - बैंक संयोजन कार्यक्रम को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मजबूत शोध की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ।

श्री आर.एन. दास, परामर्शदाता एवं डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वित्तीय समावेश एवं उद्यमशीलता केन्द्र (सी एफ आई ई), एन आई आर डी एवं पी आर द्वारा सेमिनार का संयोजन किया गया ।

मिशन अंत्योदया, ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन अंत्योदया, ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाडा पर चर्चा करने के लिए देश के सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों एवं एन आई आर डी एवं पी आर से वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया । 6 सितम्बर, 2017 को आधे दिन के लिए दिल्ली में चर्चा की गई, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन अंत्योदया के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर चर्चा की।

चर्चा के दौरान मिशन अंत्योदया के केन्द्रीय उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा गया कि एक करोड ग्रामीण परिवारों को गरीबी से बाहर निकालना है और मिशन अंत्योदया के पहले चरण में वर्ष 2020 तक 50,000 ग्राम पंचायत / 5000 समूहों को निर्धनता मुक्त बनाना है ।

सरकार ने ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाडा के दौरान ग्राम पंचायतों की आधारभूत जानकारी संग्रहित करने का निर्णय लिया और इस कार्य को 1 से 15 अक्तूबर, 2017 तक करना निर्धारित किया गया ।

विभिन्न स्तरों पर अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना पूर्वापेक्षित मानदंड रहा है । इसीलिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सर्वेक्षण से जुडे चयनित कार्यकर्ताओं का चयन करने के काम को एनआईआरडी एवं पीआर के संपूर्ण पर्यवेक्षण और निर्देश से किया गया ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से एन आई आर डी एवं पी आर द्वारा 9 सितम्बर, 2017 को एन आई आर डी एवं पी आर, हैदराबाद में मिशन अंत्योदया, ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा पर एक दिवसीय परिचयात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में 26 राज्यों, 3 संघ शासित क्षेत्रों से 84 राज्य सरकार के पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी एवं 34 एन आई आर डी एवं पी आर के संकाय सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अन्य राज्य एवं जिला-स्तरीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्र-स्तरीय स्रोत व्यक्तियों के रुप में पूरे देश का निर्माण करना रहा है । इस प्रशिक्षण के दौरान, सभी प्रतिभागियों को मिशन अंत्योदया, ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा की अवधारणों से परिचित कराया गया और वे डाटा संग्रहण एवं निगरानी के लिए उल्लिखित कार्यक्रम के विभिन्न अनुप्रयोगों से परिचित हुए । कार्यक्रम के दौरान, ग्रामीण विकास मंत्रालय और एन आई सी ने राज्यों से कहा कि मिशन अंत्योदया, ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाडा और समृद्धि ऐप, स्वच्छता ऐप एवं कौशल ऐप जैसे संबंधित अनुप्रयोगों से संबंधित पूरे अभ्यास के लिए एक पक्की कार्य योजना बनायी जाए ।

अंत्योदया के साथ जुडे एच आर के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाई गई और कैसकेडिंग पद्धति में इसका आयोजन किया गया । विवरण नीचे दिया गया है :

- एस आर एल एम / एस आई आर डी से व्यावसायियों का चयन किया गया । प्रत्येक राज्य ने एस आई आर डी / एस आर एल एम से 5-6 स्रोत व्यक्तियों के एक दल की शिनाख्त की। इन स्रोत व्यक्तियों का चयन विशेष रुप से गहन सहभागी योजना अभ्यास (आईपीपीई-11) के कार्यान्वयन में अनुभव प्राप्त लोगों में से किया गया ।
- राष्ट्र स्तरीय दल के सदस्यों ने शिनाख्त जिला स्रोत व्यक्तियों को उनके संबंधित राज्यों में प्रशिक्षण दिया । प्रत्येक राज्य के लिए 2 से अधिक राष्ट्रीय स्रोत व्यक्तियों को जिलों के स्रोत व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का काम सौंपा गया ।
- जिला स्रोत व्यक्तियों ने प्रगणक के रुप में क्षेत्र स्तरीय डाटा संग्रहण हेतु गैर-एन आर एल एम जिलों में ग्रामीण रोजगार सेवकों एवं एन आर एल एम जिलों के गहन क्षेत्रों में सी आर पी के लिए प्रशिक्षण दिया। इसी समय राज्य सरकारों ने डाटा संग्रहण एवं योजना अभ्यास में मदद के लिए तकनीकी संस्थानों से छात्रों को शामिल किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक ग्राम पंचायत के लिए सी आर पी के प्रत्येक दल के साथ एक छात्र को शामिल करने की कल्पना की । सी आर पी और जी आर एस के साथ-साथ इन छात्रों को भी प्रशिक्षित किया गया।

14 सितम्बर, 2017 से 15 अक्तूबर, 2017 तक, 25 राज्यों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किया। पश्चिम बंगाल ने 17-18 अक्तूबर, 2017 को कार्यक्रम का आयोजन किया । संबंधित राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास विभाग और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से राज्य ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा अधिकांश राज्य ने प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण का आयोजन किया। ऐसे कुछ राज्य है जो विभिन्न कारणों से टी ओ टी का आयोजन नही कर पाए अर्थात स्थानीय निकाय चुनाव के कारण सिक्किम एवं मणिपुर ने कार्यक्रम का विलंब किया है और पंजाब ने अब तक कोई तारीख निर्धारित नही की है ।

एन आई आर डी एवं पी आर में पुर्ननिर्मित खेल परिसर का उद्घाटन

गांधी जयंती पर एन आई आर डी एवं पी आर में महात्मा गांधी की मूर्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉ. डब्ल्यू.आर.रेड्डी, आई ए एस, महानिदेशक

श्री एस.एस. अहलुवालिया, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री,

एनआईआरडीएवंपीआर कार्यक्रम

एन आई आर डी एवं पी आर में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एवं पीआर), हैदराबाद में 31 अक्तूबर, 2017 को राष्ट्रीय एकता दिवस नैशनल यूनिटी डे मनाया गया । श्री सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत गणराज्य में रियासतों के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभायी थी की जयंती के उपलक्ष्य मनाया गया । राष्ट्रीय एकता दिवस को डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आई ए एस, महानिदेशक, एन आई आर डी एवं पी आर ने एन आई आई आर डी एवं पी आर के कर्मचारियों एवं छात्रों को राष्ट्रीय एकता शपथ दिलायी । उन्होंने एकता के लिए दौड हेतु झंडी दिखायी जिसमें कर्मचारियों एवं पी जी डी आर डी एम के छात्रों सहित 300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया और महानिदेशक ने दौड का नेतृत्व किया। सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता संदेश वाली टोपी पहन कर राष्ट्रीय एकता संदेश वाली प्लाईकार्ड दौड़ "हमारा मानना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को वास्तविक संभावित खतरों का सामना करने के लिए हमारे राष्ट्र में निहित शक्ति और व्यवहार्यता की पुन:पुष्टि करने का अवसर प्रदान करेगा" पकडा था।

एन आई आर डी एवं पी आर में सतर्कता जागरुकता सप्ताह

भारत सरकार ने किया एन आई आर डी एवं पी आर का दौरा

केरल प्रशासनिक आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एन आई आर डी एवं पी आर का दौरा

सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन संचार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास केन्द्र की प्रोफेसर तथा अध्यक्ष डॉ. ज्ञानमुद्रा के संपूर्ण मार्गदर्शन में एन आई आर डी एवं पी आर और युनिसेफ की संयुक्त पहल, संचार संसाधन इकाई (सी आर यू) द्वारा सितंबर और अक्तूबर 2017 के दौरान बाल अधिकार और बाल संरक्षण के लिए 'सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन संचार' पर ग्राम पंचायत के प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । प्रायोगिक रुप में, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी तथा प्रकाशम और तेलंगाना के अदिलाबाद, सिद्धिपेट एवं महबूबनगर के सरपंचों के लिए किया गया । डी सी पी ओ, सी डब्लू सी सदस्य, एन जी ओ कार्यकर्ता, सरपंच और आई सी डी एस पर्यवेक्षक जैसे प्रशिक्षकों को मॉडयूल पर एन आई आर डी एवं पी आर में तीन दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया गया और जिलों में प्रभावी रुप से लक्ष्योन्मुख प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। कुल 425 सरपंचों ने और आई सी डी एस एवं पंचायती राज विभागों से 191 अन्य प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया । इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण मुद्दों पर ग्राम पंचायत के सरपंचों की क्षमताओं के बारे में जानकारी देना समर्थ बनाना और शिशु अनुकूल गांव निर्माण के लिए विभिन्न परिस्थितियों में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर व्यवस्था स्थापित करने के बारे में उन्हें सक्षम बनाना था ।

एस एक दिवसीय प्रशिक्षण का मुख्य बल सरपंच, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एस बी सी सी रणनीतियों का आयोजन कैसे कर सकते हैं और बच्चों के मुद्दों के प्रति ग्रामीणों के रुख और व्यवहार को बदलने पर था हैं । सदस्यों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय, महिला उम्मीदवार और पहली बार निर्वाचित सदस्यों से प्रतिनिधित्व जैसे मानदंड के आधार पर चुना गया आदि बातों पर ध्यान दिया गया ।

प्रशिक्षण का समापन गांवों के सरपंचों के क्षेत्र के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की शपथ के साथ हुआ । पंचायती राज संस्थानों के अध्यक्षों ने बच्चों के लिए अनुकूल गांवों के निर्माण की दिशा में कार्य करने की जरुरत को अभिव्यक्त किया, जहाँ प्रत्येक बच्चा शोषण से मुक्त है और उसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं मनोरंजन मिलता है । बच्चों के अनुकूल गांव जहाँ है वहाँ बच्चों की सुनी जाती है और सुरक्षा दी जाती है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में चर्चित बाल मैत्री गांवों के संचालन की प्रक्रिया निम्नलिखित रुप में है :

- ग्राम बाल सुरक्षा समितियों का गठन
- बच्चों से संबंधित जाति, लिंग, आयु-वार डेटा का संग्रहण
- स्कूलों में सभी स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रवेश
- श्रम से बच्चों को दूर रखना
- सबसे कमजोर बच्चों का मानचित्रण
- स्थानांतरण के भीतर एवं बाहर के बच्चों और लापता बच्चों का पता लगाना
- जन्म पंजीकरण
- विवाह पंजीकरण

संचार संसाधन इकाई बाल संरक्षण के मुद्दों को संबोधित करते हुए संचार उत्पादों को विकसित और साझा करके बच्चों के अनुकूल गांवों के निर्माण में इन 500 पंचायतों की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना समर्थन बढाएगी ।

सी आर यू टीम से आन्ध्र प्रदेश राज्य पूर्वी गोदावरी के संयोजन श्री. श्रीनिवास, श्रीमती मृदुला ने किया और पश्चिम गोदावरी का संयोजन श्रीमती प्रीति, श्रीमती मृदुला ने किया और प्रकाशम जिले का संयोजन श्री. श्रीनिवास ने किया और तेलंगाना राज्य के महबूबनगर प्रशिक्षण सत्र श्रीमती प्रीति ने और अदिलाबाद के श्री. श्रीनिवास ने किया और सिद्धिपेट के प्रशिक्षणों का संयोजन श्रीमती मृदुला ने किया ।

ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाये रखना और स्वच्छ भारत मिशन पर प्रशिक्षण

भारत के ग्रामीण घरों में निर्मित घरेलू अपशिष्ट (ठोस एवं तरल दोनों) गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है । शौचालय निर्माण और उपयोग के मामले में प्रगति, भारत के लगभग सभी राज्यों द्वारा काफी प्रभावशील है । स्वच्छ भारत मिशन की सुविधाप्रदाताओं के लिए फिलहाल चुनौतियाँ खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना है और शौच मुक्त गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रगति करना है । सी आर आई ने 'ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त की स्थिरता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । 23 से 27 अक्तूबर 2017 तक एन आई आर डी एवं पी आर के परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पच्चीस यूनिसेफ (ओडिशा और तेलंगाना) के पैनल के सी एल टी एस प्रशिक्षक और स्वच्छता में स्वतंत्र प्रशिक्षक ने इस प्रशिक्षण में सहभाग लिया । इस कार्यक्रम के विषय थे :

- ओ डी एफ स्थिरता के दिशा निर्देश
- खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाये रखने की जाँच कैसे की जाती है?
- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित अपशिष्ट और अपशिष्ट के प्रकार को समझना
- ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विधि द्वारा मॉडल
- संचालन नियोजन : अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था, पृथक्करण एवं परिवहन
- प्रौद्योगिकी पर्याय : संग्रहण पद्धतियाँ, व्यवहार एवं अंतिम निपटान
- ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डी पी आर तैयारी

इस कार्यक्रम के दौरान, श्री. एस.एस. अहलूवालिया, राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने दौरा किया और सहभागियों के साथ बातचीत की । कार्यक्रम के भाग के रुप में, प्रतिभागियों को आर टी पी के स्वच्छता पार्क एवं कृमि खाद्य इकाई और परिसर में रसोई अपशिष्ट से संचालित बॉयो - मिथेन संयंत्र का दौरा कराया गया । सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के दौरान हर सुबह आर्ट ऑफ लिविंग सत्र में सहभाग किया ।

समुदाय संचालित ग्रामीण विकास पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामाजिक विकास के लिए लोगों को विकास प्रक्रिया के सम्मुख रखने की आवश्यकता है । यह समुदाय के विकास के हस्तक्षेप में गरीबों और सामुदायिक भागीदारी के सामाजिक समावेशन की मांग करता है जिसे समुदाय संचालित विकास कहा जाता है । 1990 के दशक में एक विकास पहल के रुप में समुदाय संचालित ग्रामीण विकास का आविर्भाव हुआ, जिसमें निर्णय लेना और प्राधिकरण जैसी विकास प्रक्रियाएँ समुदाय के हाथों में हैं। अंतर्निहित समझ यह है कि समुदाय का अपने लोगों के जीवन और आजीविका को समझना और उनके बारे में और सुधार करने की रणनीतियों को समझना और योजना बनाना उत्तम निर्णय है । समुदाय संचालित ग्रामीण विकास में, समुदाय को दिए गए संसाधनों और जानकारी के आधार पर समुदाय अपनी विकास परियोजनाओं की योजना करता है और समुदाय कार्यान्वयन एजेंसी और विकास का लाभार्थी है । यहां लोग उनकी आवश्यकताओं को संभव बनाने के लिए स्वयं को संगठित करके काम करते हैं । वे कार्यो की योजना और रुपरेखा बनाते हैं जिसमें संसाधनों का नियंत्रण समुदाय को सौंप दिया जाता है । परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और जवाबदेहिता भी कार्यान्वयनकर्ता द्वारा की जाती है जो उसके लाभार्थी भी हैं । इस प्रकार, लोगों की भागीदारी सी डी डी की कुंजी है और स्थानीय लोगों ने परियोजना में अपने श्रम का योगदान करके सहभाग किया और परियोजनाओं के प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण में शामिल हुए । सी डी डी में भागीदारी नियोजन, डिजाइन, परियोजना के कार्यान्वयन, सूचना का साझाकरना, निर्णय करना, मॉनिटरिंग और समुदाय के सशक्तिकरण के लिए प्रमुखता में संचार के प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है ।

इस दृष्टिकोण पर बल देते हुए, विश्व बैंक ने अधिक जवाबदेहिता को बढ़ाने, समानता को बढावा देने, समग्रता, दक्षता, समुदाय में सुशासन को बढावा देने, भ्रष्टाचार को कम करने, संसाधनों का दुरुपयोग, बेहतर गुणता एवं लागत और वस्तु एवं सेवाओं के भुगतान की समुदाय की इच्छा को बढावा देने के लिए इस दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर बल दिया । विश्व बैंक ने निम्न से मध्य आय, संघर्षग्रस्त देशों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि जल एवं स्वच्छता की पहुँच, स्कूलों और स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण और सामान्य रुप में ग्रामीण अवसंरचना के विकास के प्रावधान की प्रतिक्रिया के प्रति समर्थन किया । इस दृष्टिकोण ने ग्रामीण क्षेत्रों में सततयोग्य विकास के लिए सफल परिणाम दर्ज किए ।

विकास के समग्र दृष्टिकोण को प्रभावित करने, लोगों को विकास प्रक्रियाओं के समक्ष खडा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास के दृष्टिकोण का समर्थन करने के उद्देश्य से, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहण करने के लिए विकास पेशेवरों, एन जी ओ, कार्यपालकों और सामाजिक वैज्ञानिकों जो ग्रामीण विकास के लिए भागीदारी के मुख्य दृष्टिकोणों में उनके कौशल एवं ज्ञान का निर्माण करना चाहते हैं के लिए 'समुदाय संचालित ग्रामीण विकास' पर चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है । इस कार्यक्रम का आयोजन विकासशील देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए किया गया है । इथियोपिया, मॉरिशस,

नामिबिया, फिलीपींस, गुयाना, मलावी और नाइजीरिया जैसे देशों के प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में सहभाग किया ।

पाठयक्रम का समग्र उद्देश्य समुदाय संचालित विकास, समुदाय की सहभागी परियोजना प्रबंधन में सहभागी विकास और उनके उपयोग की संकल्पनाओं पर समझ को बढाना था । स्थायी समान रुप में गरीबी पर काबू पाने और संसाधनो के प्रभावी उपयोग के साथ समुदाय संचालित ग्रामीण विकास और उसके हस्तक्षेपों पर ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है ।

कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में समुदाय संचालित ग्रामीण विकास, भारतीय समाज: ग्रामीण विकास समुदाय के विषय में समस्याएँ एवं चिंताएँ, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर अवलोकन, ग्रामीण विकास के लिए आई सी टी में विशेषज्ञता वाले प्रख्यात स्त्रोत व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया । समुदाय संचालित ग्रामीण विकास और समुदाय विकास में लोगों की सहभागिता पर धारणाओं एवं अनुभूतियों पर विचार-विमर्शो का आयोजन किया गया । महिलाओं की मानव तस्करी और यौन उत्पीडन के प्रबंधन में सामुदायिक हस्तक्षेप का सैमौल उडांग के मामले की भी चर्चा की गयी । श्री श्रीराम तरनिकांती, मुख्य निर्वाचक अधिकारी, त्रिपुरा सरकार, डॉ. बेजवाडा विल्सन, श्रीमती सुकन्या, युनिसेफ, डॉ. पक्की रेड्डी, ई डी, कृषि बायोटेक फाउंडेशन और श्री. महेश भागवत, आयुक्त सायबराबाद आदि जैसे प्रख्यात स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम के इनपुट प्रदान किए गए ।

सामुदायिक विकास में लोगों की सहभागिता के लिए एक मॉडल के रुप में सहकारी समितियों का अध्ययन करने के लिए पोचमपल्ली क्षेत्र दौरा, सामुदायिक विकास के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा हस्तक्षेपों का अध्ययन करने के लिए मॉडल गांव - मेदक मरकापुर का दौरा जैसे क्षेत्र दौरों का आयोजन किया गया और मेघालय के एशिया - मॉवलीनांग में स्वच्छ गांव का प्रदर्शन कराने के लिए एक सप्ताह का दीर्घकालिक क्षेत्र दौरा आयोजित किया गया ।

अध्ययन सामग्री के साथ, सहभागियों ने नाईजिरिया के सहभागी समुदाय संचालित विकास और सतत योग्य ग्रामीण विकास, इथियोपिया के कृषि सहकारी समितियों में महिलाओं की सहभागिता, क्वारा राज्य, नाईजिरिया के विश्व बैंक सहायता प्राप्त समुदाय संचालित परियोजना कार्यान्वयन, ग्रामीण जल आपूर्ति में समुदाय सहभागिता, उत्तरी केरल से घरेलू डेटा का उपयोग करके विश्लेषण, मूलभूत सेवाओं को संबोधित करने में सहकारी समितियों के जरिए समुदाय सहभागिता : फिलीफाइन के अनुभव आदि पर कई मामला अध्ययनों पर कार्य किया ।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों से कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. जी. वैलेंटिना, एसोसिएट प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र ने किया ।

सूचना प्रौद्योगिकी और परियोजना प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीआईसीटी) ने 9 से 13 अक्तूबर, 2017 तक एन आई आर डी एवं पी आर हैदराबाद में "सूचना प्रौद्योगिकी और परियोजना प्रबंधन" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया । देश भर में 8 राज्यों से 22 कर्मचारियों ने सहभाग किया और इस कार्यक्रम का लाभ उठाया जिनमें ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन महिला अधिकारी, डी आर डी ए, आर आई आर डी, पी एम ए वाई, मृदा संरक्षण एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, वानिकी तथा पर्यावरण और बागवानी विभाग के कर्मचारी शामिल थे ।

यह कार्यक्रम मुख्यत: ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जिला परिषदों, डी आर डी ए / एस आई आर डी / आर आई आर डी / ई टी सी, आवास और संबंधित विभागों जैसे कि कृषि, वानिकी एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य मिशन, जल संसाधन आदि के कर्मचारियों को संवेदित एवं सशक्त करने और शासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, परियोजना प्रबंधन के साधनों एवं तकनीको का उपयोग करने, विशेषतया ग्रामीण विकास, ई-शासन, भू-संसूचना के उसके अनुप्रयोग की आवश्यकता के लिए भी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन को सुकर बनाने और सूचना प्रणालियों के विकास में कौशल प्रदान करने पर केन्द्रित था ।

सूचना प्रणालियों के विकास, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के लिए भू-संसूचना, परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित विषयों के अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी और परियोजना प्रबंधन की क्षमता में बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए ई-शासन परियोजनाओं, नेतृत्व कौशल, सामर्थ्य और खुला स्त्रोत सॉफ्टवेयर की जरुरत पर भी चर्चा की गयी थी । प्रतिभागियों को एन आई आर डी एवं पी आर के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क के लिए दौरे का अवसर प्रदान किया गया । प्रतिभागियों ने एन आई आर डी एवं पी आर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम में भी सहभाग किया । कार्यक्रम ने सराहा प्राप्त की और प्रतिभागियों ने यह व्यक्त किया कि ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संयोजन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सी आई सी टी) केन्द्र के वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर श्री जी.वी. सत्यनारायण ने किया ।

बी वी बी वी स्कूल - एन आई आर डी एवं पी आर में हिन्दी दिवस समारोह

हिन्दी दिवस - पुरस्कार वितरण 31 अक्तूबर,2017 को बी वी बी वी स्कूल - एन आई आर डी एवं पी आर में आयोजित किया गया । श्रीमति मालती रेड्डी, अध्यक्ष, महिला मंडली, एन आई आर डी एवं पी आर और सागर ग्रूप शिक्षा संस्थान की सचिव इस समारोह की मुख्य अतिथि थी और उन्होने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए । इस समारोह में श्रीमती अनिता पांडे, सहायक निदेशक, हिन्दी अनुभाग, एन आई आर डी एवं पी आर एवं श्री ई. रमेश भी उपस्थित थे । इस अवसर पर स्कूल की पत्रिका "विद्या द्वीप" का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि ने किया और उन्होंने बच्चों द्वारा किए गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों की सराहना की ।

श्रीमती डब्ल्यू मालती रेड्डी ने हिन्दी भाषा के इतिहास पर भाषण दिया और उन्होंने कर्मचारियों तथा स्कूल के छात्रों को इन कारणों को स्पष्ट किया कि क्यों हमने हिन्दी को राजभाषा के रुप में चुना । उन्होंने शिक्षको के साथ-साथ छात्रों के प्रयासों की भी सराहना की ।

बी वी बी वी स्कूल के छात्रों ने इस कार्यक्रम में उत्साह से भाग लिया । दसवीं कक्षा के छात्र अभय सिंह ने हिन्दी भाषा के महत्व तथा उसकी महानता और हमारे रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बात की। सभी बच्चों में बाल शोषण के प्रति जागरुकता लाने में दसवीं कक्षा की छात्राओं ने नुक्कड नाटक का प्रदर्शन भी किया ।

हिन्दी समारोह जिसे 1 से 14 सितम्बर तक मनाया गया के अवसर पर कविता पाठ, कहानी, काव्य-लेखन, प्रश्नोत्तरी आदि जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । समारोह में इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए । बी वी बी वी स्कूल के प्रधानाचार्य, श्री बी. रवि किरण ने मुख्य अतिथि और एन आई आर डी एवं पी आर के संकाय को बधाई दी ।

नागारम समूह के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा पर परामर्शी बैठक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यों के तहत हितधारियों के साथ 24 अक्तूबर, 2017को सूर्यापेट जिले के नागारम मंडल के फनगिरी गाँव के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा पर एक परामर्शी बैठक का आयोजन किया ।

बैठक की अध्यक्षता तेलंगाना राज्य के सूर्यापेट जिले के जिला शैक्षिक अधिकारी, श्रीमती बी. वेंकटा नरसम्मा ने की । बैठक का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 65 सदस्य जिनमें ग्राम पंचायतें, स्कूल प्रबंधन समितियाँ, महिला स्व-सहायता समूह, मध्याह्न भोजन योजना के बावर्ची - सह- सहायक नागारम मंडल के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यपकों, शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों और माता-पिता शामिल थे ।

परामर्शी बैठक का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा के सुधार के लिए रणनीतिक योजना बनाना था । बैठक की शुरुआत "सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा में सुधार कैसे करें" पर प्रस्तुतीकरण के जरिए डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास केन्द्र ने किया । उन्होंने स्कूल विकास में समुदाय सहभागिता और एस एम सी की सक्रिय भूमिका पर ध्यान दिया । सभी हितधारियों ने सक्रियता से सहभाग किया और सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा पर बातचीत की । स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों ने कहा कि उन्हें शिक्षा योजनाएँ और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में समझ नहीं है । इसके अलावा, उन्होंने कहाकि, यदि वे स्कूल की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं , तो वे शिक्षा के विकास कार्य के निर्वहन के लिए तैयार हैं । इसके अलावा एसएमसी सदस्यों ने क्षमता निर्माण की क्रियाकलापों का आयोजन करने के लिए प्राधिकरणों से निवेदन किया । शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों ने गुणवत्ता शिक्षा पर चर्चा की और यह दोहराया कि आधारभूत संरचना और देखरेख की कमी गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है ।

सूर्यापेट जिले के जिला शैक्षिक अधिकारी ने गुणवत्ता शिक्षा के जरिए गरीब बच्चों के उन्नयन हेतु प्रयास करने के लिए शिक्षकों से निवेदन किया । नागारम मंडल के तहसीलदार ने सरकारी स्कूलों के कार्य पर बात करने समय, गुणवत्ता शिक्षा की सुपुर्दगी में शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया । मंडल शिक्षा अधिकारी ने सरकारी स्कूलों की वर्तमान स्थिति दर्शायी और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने में सहयोग करने के लिए हितधारियों से निवेदन किया ।

डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएचआरडी, एन आई आर डी एवं पी आर ने हितधारियों के विचारों को समेकित किया और नागारम समूह के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा सुधारने के लिए रणनितिक योजना की तैयारी के लिए उभरते परिदृश्य को प्रस्तुत किया ।

परामर्शी बैठक का समापन मंडल शिक्षा अधिकारी, नागारम के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ । उसी दिन, एन आई आर डी एवं पी आर की टीम के साथ जिला शिक्षा अधिकारी ने सूर्यापेट जिले के जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट से भेंट की और सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा के सुधार के लिए परामर्शी बैठक एवं उभरती स्थिति पर बातचीत की । श्री राजेश्वर, सहायक प्रोफेसर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केन्द्र ने गुणवत्ता शिक्षा के सुधार में डिजीटल साक्षरता और आईसीटी अनुप्रयोगों पर ध्यान दिया । जिला प्रशासन के परामर्श से तीन वर्षो के लिए शिक्षा की रणनीतिक योजना बनाने के लिए जिला कलक्टर ने एन आई आर डी एवं पी आर की टीम से निवेदन किया ।

उद्दीपना पहल के तहत प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए बाल शिक्षा-शास्त्र पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

उद्दीपना (सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करनेवाली एक पहल) के जरिए सुदृढ सार्वजनिक शिक्षा के भाग के रुप में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने प्रथम शिक्षा फाउंडेशन पारकेटपल्ली, नलगोन्डा जिला, तेलंगाना राज्य के सहयोग से प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए बाल्यावस्था शिक्षा अध्यापन-शास्त्र पर तीन दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन किया । 3 से 10 वर्ष की आयु के समूह बच्चों में शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और भाषागत विकास के क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए विशेष रुप में स्कूल पूर्व एवं पूर्व प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं को सुदृढ करने के लिए प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की प्रभावशीलता सुधारने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया गया । नलगोंडा जिला प्रशासन के समर्थन से माननीय एसएलए श्री वेमुला वीरेशम ने नकरेकल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में उद्दीपना कार्यक्रम को प्रवर्तित किया है ।

मदर टेरेसा ग्रामीण विकास सोसायटी में नरकेटपल्ली मंडल मुख्यालयों में 26 से 28 अक्तूबर, 2017 तक प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए ईसीई अध्ययन शास्त्र पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया था । उद्दीपन पहल ने नकरेकल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के छह राजस्व मंडल अर्थात नकरेकल, चिटयान,नरकेटपल्ली, केथपल्ली, रामन्नापेट और कट्टांगुर को कवर किया है । प्रत्येक मंडल से आठ मास्टर प्रशिक्षकों (4 शिक्षकों और 4 स्वयं सेवकों) को परिलक्षित किया गया । अत: कुल 48 मास्टर प्रशिक्षकों ने कार्यक्रम में सहभाग किया ।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री गौरव उप्पल, आई ए एस, जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नलगोंडा ने 26 अक्तूबर, 2017 को किया । उनके उद्घाटन भाषण में जिला कलक्टर ने बाल्यावस्था पूर्व शिक्षा और सततयोग्य विकास लक्ष्य 4 अर्थात समावेशी एवं समता गुणवत्ता शिक्षा हासिल करने के महत्व को रेखांकित किया । उन्होंने ईसीई पर शिक्षकों के लिए अध्यापन-शास्त्र प्रशिक्षण की जरुरत की यथासमय मान्यता के लिए एन आई आर डी एवं पी आर और प्रथम की भूमिका की भी सराहना की और उनकी सराहना की अभिव्यक्ति की । डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास केन्द्र, एन आई आर डी एवं पी आर और उद्दीपन पहल सलाहकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के बारे में जानकारी दी और गुणवत्ता शिक्षा की प्रासंगिकता पर बल दिया ।

उद्दीपना पहल के अध्यक्ष, श्री वेमुला विरेशम, नकरेकल विधानसभा चुनाव क्षेत्र के एमएलए ने गरीब बच्चों तक गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी स्कूलों को सुदृढ करने की आवश्यकता पर जोर दिया और गुणवत्ता शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में सरकारी स्कूलों को उद्दीपना पहल में परिणत करने में सहायता करने के लिए एन आई आर डी एवं पी आर के महानिदेशक और प्रथम संगठन को अपना धन्यवान व्यक्त किया । श्री पूला रविंदर, विधान परिषद सदस्य (नलगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) तेलंगाना ने, उनके भाषण में सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के महत्व और कक्षाओं के डिजिटलीकरण के महत्व को स्पष्ट किया और उद्दीपना पहल के लिए आई सी टी समर्थन बढाने के लिए एन आई आर डी एवं पी आर से निवेदन किया । श्रीमती बी.एल. सुनिता, कार्यक्रम प्रमुख, प्रथम ने ईसीई के महत्व और गुणता शिक्षा को बढावा देने में आंगनवाडी केन्द्रों के साथ एकजुट स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया । सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई सी ई अध्यापन-शास्त्र के अध्यापन कौशल की सख्त जरुरत है ।

सरकारी प्राथमिक स्कूलों के साथ-साथ आंगनवाडी केन्द्रों में स्कूल पूर्व घटकों की वर्तमान स्थिति, सततयोग्य ग्रामीण विकास लक्ष्य - 4 पर विवरण जो सभी और उसकी उपलब्धि के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्ता शिक्षा है, मानव विकास में पूर्व बाल्यावस्था का महत्व, समग्र विकास एवं स्कूल पूर्व शिक्षा, ग्रामस मोटर एवं फाइन मोटर विकास के लिए भौतिक एवं मोटर विकास क्रियाकलाप सामाजिक विकास बच्चों में समूहीकरण, कौशल सुधारने के क्रियाकलाप, विकास क्रियाकलाप एवं कविता लेखन (ध्वनि, गंध, स्मृति,

श्रेणीकरण, मिलान और अनुक्रमण) अनुक्रमिक शिक्षण, अवधारणा एवं क्रियाकलाप की समझ पर यह कार्यक्रम केन्द्रित था । क्रियाकलाप पुस्तक और कार्यपत्रकों का स्पष्टीकरण, बाल्यावस्था पूर्व शिक्षा का मूल्यांकन और शिशु रिपोर्ट कार्ड, बच्चों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यकर आदतों का विकास जैसे कि शौचालयों का उपयोग और हाथ साफ आदि धोने विषय भी इस कार्यक्रम में थे । यह अध्यापन-शास्त्र अध्यापन और शिक्षा के दृश्य श्रव्य उपकरणों के साथ छोटे समूह एवं व्यक्तिगत गतिविधियों के माध्यम से अधिकतर सिखाया जाता है ।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्रोत व्यक्तियों को आमंत्रित कर इसे 20 सत्रों में तैयार किया गया, स्रोत व्यक्तियों में प्रथम से श्रीमती बी.एल. सुनिता, श्रीमती के. करुणा, श्रीमती सी. श्रीदेवी, श्रीमती वाई. सावित्री, डी आई ई टी, नलगोंडा सरकार से श्री आर. मंगारेड्डी और स्वच्छ आंध्र मिशन, आंध्र प्रदेश सरकार से श्री एल. वेंकटेश्वर राव आदि आमंत्रित थे ।

टी ओ टी प्रशिक्षण का समापन 28 अक्तूबर, 2017 को हुआ । समापन सत्र में श्री वेमूला विरेशम, माननीय एम एल ए, नकरेकल निर्वाचन क्षेत्र ने मास्टर प्रशिक्षकों को संबोधित किया और इस प्रशिक्षण से अध्ययनों को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी स्कूलों में अध्यापन की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों से अपील की । एम एल ए ने क्रियाकलाप किताबों का विमोचन किया और उपरोक्त विषयों पर विभिन्न स्कूलों के लिए स्कूल पूर्व टी एल एम किट का वितरण किया और शिक्षकों ने उनके स्कूलों में ई सी ई अध्यापन-शास्त्र का उपयोग करने के लिए 10 दिनों की कार्य योजना बनाई। कार्यक्रम का समापन उद्दीपना पहल के अध्यक्ष के संबोधन से हुआ । इस कार्यक्रम का संयोजन डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, एन आई आर डी एवं पी आर और उद्दीपना पहल के सलाहकार, श्री आर. मंगा रेड्डी, व्याख्याता सरकारी डी आई ई टी, नलगोंडा, श्री जी. सुरेश, मंडल परिषद विकास अधिकारी, नकरेकल और श्री के. नरसिम्हा, मंडल शिक्षा अधिकारी, नरकेटपल्ली, नलगोंडा जिला ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी, आई एस एस, महानिदेशक, एन आई आर डी एवं पी आर ने की ।

ग्रामीण भारत में जेडर और कार्य पर प्रोफेसर रितू दीवान द्वारा विशेष व्याख्यान

श्री एस.आर. शंकरन की 83 वीं जयंती के अवसर पर, एस आर शंकरन चेयर, एन आई आर डी एवं पी आर ने 25 अक्तूबर, 2017 को "ग्रामीण भारत में जेंडर और कार्य" पर एक सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया प्रोफेसर रितू दिवान, अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्ययन संगठन, पूर्व निदेशक अर्थशास्त्र विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केन्द्र (जेंडर अर्थशास्त्र), अर्थशास्त्र विभाग ने व्याख्यान दिया ।

प्रोफेसर दीवान ने उनके व्याख्यान में ग्रामीण कार्यक्षेत्र में जेंडर के हाशिए के मुद्दों को संदर्भित किया । महिला श्रम शाक्ति भागीदारी केवल कम नहीं है बल्कि हाल में इसमें महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है । हालांकि ग्रामीण महिलाएँ बडी संख्या में आर्थिक क्रियाकलापों में लगी हुई हैं, उन्हें कमजोर समझा जाता हैं और बडे पैमाने पर अदृश्य रहती हैं । अफसोस की बात यह है कि, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली भी विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में

महिलाओं के कार्य को पर्याप्त रुप से ग्रहण नहीं करती है । अपने वक्तव्य में उन्होंने इन मुद्दों के बारे में चिंता जताई और साथ ही ग्रामीण भारत में महिलाओं के काम को समझने और उन्हें मूल्य देने के बारे में वैकल्पिक निर्णायक बातें बतायी ।

उन्होंने परिवार, राज्य और सामाजिक मानदंडों सहित विभिन्न संस्थानों और उनकी आपसी क्रियाएँ जो महिलाओं के काम को कम समझते हैं और कम मानते है की भूमिका पर चर्चा की। संसाधनों तक असमान पहुँच, राजनैतिक और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कम सहभागिता ने रोजगार के बाजार में उनकी भूमिका को दुर्बल बना दिया । जेंडर कार्य संबंध भी सामाजिक मानदंड, पितृसत्तात्मक मानसिकता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से प्रभावित हो जाता है । उन्होंने राज्य की वापसी को भी उजागर किया जिसमें महिलाओं से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर सार्वजनिक व्यय में भारी कटौती शामिल है । उन्होंने महिलाओं के काम को पहचान दिलाने और सम्मान दिलाने हेतु अधिक प्रकट रुप में मजबूत स्थिति बनायी है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को सक्षम करने और अधिक समान समाज की कल्पना करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम होगा ।

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
संपादक : डॉ. के. पापम्मा
फोटोग्राफ : पी. सुब्रमण्यम

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030 की ओर से
डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी

मुद्रण :
वैष्णवी लेजर ग्राफिक्स, बरकतपुरा, हैदराबाद,
फोन: 040-27552178

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
NIRDPR
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030
टेलीफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल: cdc.nird@gov.in, वेबसाईट : www.nird.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम